problem. I urge upon the Government to create a unified law on industrial accidents. This law should streamline existing regulations, establish a centralized database for chemical risks, and ensure stringent enforcement of safety standards. It should also mandate proper training for workers and adequate investment in safety infrastructure. We owe it to our hardworking industrial workforce to ensure their safety and well-being.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Now Shri Neeraj Dangi.

श्री नीरज डांगी: उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, मेरा माइक ऑन नहीं है।

श्री उपसभापति: आपके पीछे माइक ऑन है। आप जहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ भी माइक ऑन है। आप जहाँ खड़े हैं, वहाँ भी माइक ऑन है।

Demand to increase the amount of Member of Parliament Local Area Development Scheme *i.e.* 'MPLAD'

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने एक महत्वपूर्ण विषय, जो इस ओर और उस ओर के सभी सांसदों के लिए महत्वपूर्ण है, इस विशेष उल्लेख के जरिए उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 'एमपीलैड' की शुरुआत 23.12.1993 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव द्वारा सभी दलों के सांसदों के आग्रह पर 5 लाख रुपये प्रति सांसद की राशि से प्रारंभ की गई थी, जिससे सांसद अपने क्षेत्र में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण सहित जनता को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें।

'एमपीलैड' फंड की राशि को वर्ष 1998-99 में 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया और 13 वर्ष पश्चात् वर्ष 2011-12 में सांसदों के आग्रह पर इसे बढ़ाकर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2011-12 के बाद 13 वर्षों में इस राशि को बढ़ाने पर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ।

महोदय, एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 8 से 10 विधान सभा क्षेत्रों का समावेश होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के अंतर्गत राशि कई वर्षों से पांच करोड़ या 5 करोड़ रुपये से अधिक है। दिल्ली में यह राशि 10

करोड़ रुपये प्रति विधायक है। 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' की राशि और 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' की राशि लगभग समान हो गई है, जबकि आनुपातिक रूप से यह राशि लगभग 8 से 10 गुना होनी चाहिए। वहीं किसी राज्य सभा सांसद के लिए पूरे राज्य में विकास योजनाओं हेतु 5 करोड़ का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष पर्याप्त नहीं है।

अतः आग्रह है कि 13 वर्ष पूर्व निर्धारित इस राशि पर पुनर्विचार करते हुए 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' की राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये प्रति सांसद किया जाना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि MPLADS की राशि 15 करोड़ रूपये करने पर विचार करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), A. A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri K.R.N. Rajeshkumar (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Government to intervene in the recent hike of import duty for exporters of oranges from Vidarbha region in Maharashtra to Bangladesh

DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE (Maharashtra): Sir, you are aware that in Maharashtra State, Amravati and Nagpur Division is recognized as Vidarbha. It is also the highest orange-fruit producer and exporter in the country. Total 1,26,000 hectares of area is occupied for production of Oranges in Amravati and Nagpur Division. Around seven lakh metric tonnes of Oranges are produced in the season of Ambiya and Mriga bahar. The farmers and producer company exporters of this Division have yearly been exporting around 1.25 to 1.50 lakh metric tonnes of Oranges to Bangladesh. But, due to hike in Import Duty by Bangladesh Government from Rs. 32 to Rs. 62 per Kg, the Orange export to Bangladesh has totally been stopped this season. Due to multiple-time hikes in Import Duty and devaluation of currency of Bangladesh, total Orange export from Vidarbha has suffered. I urge upon the Government to look into the matter and impress upon the Government of Bangladesh to reduce the Import Duty or support Orange exporters by providing 25 to 30 per cent subsidy to continue Orange export to Bangladesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with